AGRASEN CIVIL SERVICES ACADEMY

Where tradition meets innovation

ACSA

1 से 7 अगस्त 2023

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

For

UPSC / RPSC EXAMS

and All Other Competitive

- एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी)
- एआरसीएल और सीडीएमडीएफ
- बेनीसागर का पुरातात्विक महत्व
- फाल्कन शील्ड-2023
- महिलाओं और महिला सेल के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं पर दिशानिर्देश
- योजना क्लासिक्स
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (MASAI) परीक्षण के साथ मैमोग्राफी स्क्रीनिंग
- स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) पोर्टल

APT

A UNIT OF
AGRAWAL PG COLLEGE
Affiliated to University of Rajasthan | Managed by Shri Agrawal Shiksha Samiti
(A Co-Educational College)

+91-8824395504, +91-8290664069
www.acsajaipur.com
Agrasen Katla, Maharaja Agrasen Marg,
Agra Road, Jaipur - 302003

Current Affairs 1 to 7 August 2023

संक्षिप्त:-

- एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी)
- एआरसीएल और सीडीएमडीएफ
- टेकइक्विटी क्या है ?
- बेनीसागर का पुरातात्विक महत्व
- फाल्कन शील्ड-2023
- महिलाओं और महिला सेल के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं पर दिशानिर्देश
- मेथनॉल से हाइड्रोजन उत्पादन की नई उत्प्रेरक प्रक्रिया:
- योजना क्लासिक्स
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
- G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रिस्तरीय बैठक
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (MASAI) परीक्षण के साथ मैमोग्राफी स्क्रीनिंग
- आयुष वीजा
- असम लकड़ी आधारित उद्योग (संवर्धन और विकास) नियम 2022
- विवाद से विश्वास 2:
- स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) पोर्टल

एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी)

एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) अगस्त में ब्रिस्बेन में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए तैयारी कर रहा है। इस प्रमुख सभा का लक्ष्य भारत में 5जी सेवाओं के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड की भविष्य की तैनाती का निर्धारण करना है। जैसा कि भारत और चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य सहित क्षेत्र के 3 सदस्य देश दुबई में विश्व रेडियो संचार-2023 सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, इस बैठक में लिए गए निर्णय 5जी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देश।

5G सेवाओं के लिए 6 GHz स्पेक्ट्रम बैंड का निर्णय लेना

ब्रिस्बेन में एपीटी बैठक का प्राथमिक उद्देश्य भारत में 5जी सेवाओं के लिए 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की तैनाती पर विचार-विमर्श करना और उसे अंतिम रूप देना है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड 10 जीबीपीएस तक इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है , जिससे तेज और अधिक कुशल संचार नेटवर्क सक्षम होता है। बैठक का उद्देश्य 5G सेवाओं के लागत प्रभावी रोलआउट के लिए 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को अपनाने के लिए सभी क्षेत्र 3 देशों से गति और सामूहिक समर्थन का निर्माण करना है।

प्रमुख क्षेत्र 3 सदस्य राष्ट्र

एपीटी बैठक में महत्वपूर्ण क्षेत्र 3 सदस्य देशों की भागीदारी होगी, जिसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में देशों का यह विविध समूह आईसीटी नीति और नियामक समन्वय को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह बैठक 5जी तैनाती के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन जाती है।

6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड में टेक दिग्गजों की रुचि

गूगल, मेटा (पूर्व में फेसबुक), अमेज़ॅन, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, क्वालकॉम, इंटेल और नेटफ्लिक्स जैसे तकनीकी दिग्गजों ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। वे वाईफाई मार्ग के माध्यम से ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इस बैंड का उपयोग करने की क्षमता देखते हैं। 10 जीबीपीएस तक की इंटरनेट स्पीड के साथ , 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम डिजिटल विभाजन को पाटने और दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती और हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है।

टेलीकॉम कंपनियों का रुख अलग-अलग

दूसरी ओर, भारत की शीर्ष टेलीकॉम कंपनियां , अर्थात् रिलायंस जियो , भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का दृष्टिकोण अलग है। वे 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करने और उसे तुरंत 5जी सेवाओं और भविष्य के 6जी प्रयासों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं । विचारों में यह मतभेद एपीटी बैठक के दौरान गहन चर्चा के लिए मंच तैयार करता है।

एपीजी की भूमिका का महत्व

एपीटी के भीतर, एशिया-प्रशांत समूह (एपीजी) को 5जी सेवाओं के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड परिनियोजन सहित सभी प्रमुख क्षेत्र 3 वायरलेस/स्पेक्ट्रम मामलों को संरेखित करने का काम सौंपा गया है। एपीजी दुबई में डब्ल्यूआरसी-2023 सम्मेलन में एक आम प्रस्ताव पेश करेगा, जिसका लक्ष्य 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना और एक लागत-कुशल 5जी डिवाइस/नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है । इन वायुतरंगों के आसपास ।

भारत की स्थिति का इंतजार

क्षेत्र 3 के कई देश आगामी एपीजी बैठक में भारत की स्थिति का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। 5जी सेवाओं के लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को तैनात करने के लिए भारत का समर्थन महत्वपूर्ण है, खासकर चीन द्वारा इसी उद्देश्य के लिए बैंड के हालिया आवंटन को देखते हुए। भारत के फैसले से क्षेत्र की 5जी रणनीतियों और स्पेक्ट्रम आवंटन पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के बारे में

6 गीगाहर्ट्ज बैंड एकमात्र मिड-बैंड स्पेक्ट्रम रेंज है जो प्रति टेलीकॉम कंपनी 300-400 यूनिट की सन्निहित बैंडविड्थ को समायोजित करने में सक्षम है । वर्ष 2030 तक दूरसंचार क्षेत्र में उभरती मांगों को पूरा करने के लिए ऐसी क्षमता महत्वपूर्ण है।

एआरसीएल और सीडीएमडीएफ

भारतीय वित्तीय बाजार में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास देखा गया है, जो तरलता, बाजार स्थिरता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों से प्रेरित है। हाल ही में एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार को और बढ़ावा देने और भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक बाजार पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थान (एआरसीएल और सीडीएमडीएफ) लॉन्च किए।

भारत के वित्तीय बाजार में महत्वपूर्ण विकासों में से एक एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (एआरसीएल) की स्थापना है। नई लॉन्च की गई संस्था कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो लेनदेन के समाशोधन और निपटान पर ध्यान केंद्रित करती है । सुचारू और कुशल रेपो सेवाओं की सुविधा प्रदान करके, एआरसीएल का लक्ष्य कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो बाजार को व्यापक और गहरा करना है। इस कदम से तरलता को बढ़ावा मिलने और परिसंपत्तियों को नष्ट किए बिना इन्वेंट्री और अल्पकालिक तरलता जरूरतों के लिए धन की पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। ARCL एक अधिक जीवंत और गतिशील कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो बाजार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि (सीडीएमडीएफ): द्वितीयक बाज़ार तरलता बढ़ाना

कॉरपोरेट बांड बाजार में द्वितीयक बाजार की तरलता बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता के कारण कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष (सीडीएमडीएफ) का निर्माण हुआ। यह फंड तनावग्रस्त और सामान्य दोनों समय में बाजार सहभागियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचे के रूप में कार्य करता है । सीडीएमडीएफ का प्राथमिक लक्ष्य निवेश-ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों को खरीदना है, जिससे बांड बाजार के विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। यह बाजार की अव्यवस्था के समय में बैकस्टॉप सुविधा प्रदान करता है, कॉर्पोरेट ऋण निवेशकों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और अधिक लचीले वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है।

बाज़ार पूंजीकरण मील का पत्थर: भारत की प्रगति

बाजार पूंजीकरण प्रभावशाली रुपये तक पहुंच गया है । 300 लाख करोड़. यह उपलब्धि देश की मजबूत वित्तीय बाजार वृद्धि का प्रमाण है। पिछले दशक में, भारत का बाजार पूंजीकरण हर पांच साल में लगभग दोगुना हो गया है, जिससे यह विश्व स्तर पर पांचवां सबसे मूल्यवान देश बन गया है। बाजार पूंजीकरण में वृद्धि निवेशकों के बढ़ते विश्वास और भारत की आर्थिक संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

IFSC: प्रत्यक्ष लिस्टिंग और वैश्विक बाजारों तक पहुंच को सक्षम करना

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) एक महत्वपूर्ण मंच है जो अपने एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की सीधी लिस्टिंग को सक्षम बनाता है। यह पहल शीघ्र ही चालू होने वाली है, जिससे स्टार्टअप और समान कंपनियों को GIFT IFSC के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी। वैश्विक बाजारों तक ऐसी पहुंच न केवल भारतीय कंपनियों को बेहतर मूल्यांकन प्रदान करती है, बल्कि वैश्विक पूंजी के लिए दरवाजे भी खोलती है, जिससे विकास और विस्तार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।

कॉर्पोरेट ऋण जारीकर्ताओं का विस्तार: आरईआईटी और इनविट

केंद्रीय बजट 2021 ने कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) जैसी नई प्रकार की संस्थाओं के लिए एक कानूनी ढांचा पेश किया। यह कदम विभिन्न संस्थाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके कॉर्पोरेट बांड बाजार में विविधता लाता है। REITs और InvITs देश के बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट क्षेत्रों में योगदान करते हैं, व्यापक निवेशक आधार को आकर्षित करते हैं और समग्र बाजार गतिविधि को बढ़ावा देते हैं।

टेकइक्विटी क्या है ?

टेकइक्विटी लॉन्च करने के लिए तैयार है - एक परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं को सशक्त बनाना है। गांधीनगर में दो दिवसीय जी20 एम्पावर शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपने आधिकारिक अनावरण के साथ , टेकइक्विटी ने आने वाले वर्ष में दो से तीन मिलियन महिलाओं को प्रभावित करने का वादा किया है।

टेकइक्विटी भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक अग्रणी पहल के रूप में उभरी है, जो लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने की कोशिश कर रही है। मंच का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं को आवश्यक डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, तकनीकी कौशल विकास और मुख्य कौशल वृद्धि पाठ्यक्रमों से लैस करके सशक्त बनाना है।

बहुभाषी पहुंच: सभी के लिए समावेशिता

TechEquity प्रभावशाली 120 भाषाओं में सामग्री की पेशकश करके समावेशिता को प्राथमिकता देता है। यह बहुभाषी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक स्थिति के बावजूद, विविध भाषाई पृष्ठभूमि की महिलाएं मंच तक पहुंच सकती हैं।

तीन साल का समर्थन: भारत की प्रतिबद्धता

अगले तीन वर्षों के लिए टेकइक्विटी को वित्त पोषित करके महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है । यह वित्तीय सहायता प्लेटफ़ॉर्म की स्थिरता और लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में निरंतर प्रयासों को सुनिश्चित करती है।

फिक्की: सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना

टेकइक्विटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार संगठन के रूप में, FICCI निर्बाध संचालन सुनिश्चित करता है और उपयोगकर्ता अनुभव को समृद्ध करता है।

सशक्तीकरण: महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व को उत्प्रेरित करना

एम्पावर, महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए जी20 गठबंधन, 2019 में स्थापित किया गया था। यह महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित जी20 गठबंधन है। यह गठबंधन शेरपा ट्रैक के तहत संचालित होता है, जो सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को एक साथ लाता है, जिसका प्राथमिक ध्यान G20 देशों में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाने पर है।

बेनीसागर का पुरातात्विक महत्व

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से 85 किलोमीटर दूर स्थित बेनीसागर गांव ऐतिहासिक आश्चर्यों का खजाना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा की गई खुदाई से इस स्थल पर पांचवीं शताब्दी ईस्वी से 16-17वीं शताब्दी ईस्वी तक निरंतर निवास का पता चला है। बेनीसागर के पुरातात्विक महत्व ने इसे 100 प्रमुख पुरातात्विक स्मारकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिलाया है।

बेनीसागर का इतिहास 1840 का है जब ब्रिटिश सेना के कर्नल टिकेल ने पहली बार इस स्थल का दौरा किया था। उनकी खोज ने क्षेत्र के प्राचीन अतीत में रुचि जगाई, जिससे इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा आगे की जांच के लिए मंच तैयार हुआ।

रहस्यमय पत्थर की सील: एक भाषाई पहेली

बेनीसागर की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक एक पत्थर की मुहर है जिस पर " प्रियंगु " लिखा हुआ है धेयम चतुर्विद्या (चतुर्विद्या)।" प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए शिलालेख ने विद्वानों और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है, जो चार वेदों में पारंगत प्रियंगु नामक एक जानकार व्यक्ति की उपस्थिति का संकेत देता है।

ऐतिहासिक काल और मंदिर वास्तुकला: अतीत की एक झलक

पुरालेखीय साक्ष्यों के आधार पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट बेनीसागर को 5वीं शताब्दी का बताती है। इसके अतिरिक्त, स्थल पर पाई गई मंदिर की वास्तुकला रेखा से मिलती जुलती है देउला प्रकार, जो ओडिशा में प्रचलित है , संभावित ऐतिहासिक संबंधों का सुझाव देता है।

एक संगीतमय पत्थर: घंटी जैसी ध्वनि

बेनीसागर की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक मंदिर के पास एक विशाल पत्थर है जो दूसरे पत्थर से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। इस पत्थर की अद्वितीय ध्वनिक संपत्ति ने स्थानीय लोगों और आगंतुकों को समान रूप से आकर्षित किया है, जिससे यह एक उल्लेखनीय आकर्षण बन गया है।

केंद्र सरकार की पर्यटन योजनाएँ: प्राचीन स्थलों के लिए आधुनिक सुविधाएँ

सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के अनुरूप, केंद्र सरकार देश भर के पुरातात्विक स्मारकों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रही है। इन सुविधाओं में एक दृश्य-श्रव्य भी शामिल है केंद्र , वाईफाई , ऑडियोरेल और एक जल प्रबंधन प्रणाली, जिसका उद्देश्य बेनीसागर जैसी साइटों पर आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाना है ।

चिरस्थायी तालाब: प्रकृति की उत्कृष्ट कृति

बेनीसागर का विशेष आकर्षण 300 गुणा 350 मीटर का एक भव्य तालाब है, जो कभी नहीं सूखता। यह उल्लेखनीय प्राकृतिक आश्चर्य प्रकृति की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है और पुरातात्विक स्थल के आकर्षण को बढ़ाता है।

फाल्कन शील्ड-2023

संयुक्त सैन्य अभ्यास और हथियार सौदों के माध्यम से अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में प्रगति कर रहे हैं। एक उल्लेखनीय अभ्यास, फाल्कन शील्ड 2023, चीन के झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में आयोजित होने वाला है।
फाल्कन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देते हुए चीनी और यूएई सेनाओं के बीच व्यावहारिक आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करना है। हालाँकि, चीनी रक्षा मंत्रालय द्वारा यूएई दल के आकार, प्रशिक्षण की अवधि और इसके दायरे के बारे में विशिष्ट विवरण का खुलासा नहीं किया गया है।

झिंजियांग संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए एक स्थल के रूप में

झिंजियांग अतीत में संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए एक पसंदीदा स्थान रहा है। 2016 में, इस क्षेत्र ने सहयोगात्मक सैन्य प्रशिक्षण के स्थल के रूप में कार्य किया जिसमें चीन की पैदल सेना इकाइयाँ और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ब्लॉक के अन्य सदस्य राष्ट्र शामिल थे। यह अभ्यास युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने, सैन्य संचार को बढ़ावा देने और सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तत्परता बढ़ाने पर केंद्रित था।

संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी और रक्षा शस्त्रागार

यूएई की वायु सेना मुख्य रूप से एफ-16 और मिराज-2000 सहित पश्चिमी लड़ाकू विमानों पर निर्भर है। हालाँकि, देश ने चीनी निर्मित हथियारों को शामिल करके अपने शस्त्रागार में विविधता लाने में रुचि दिखाई है। 2011 में, चीन ने संयुक्त अरब अमीरात को कम से कम पांच विंग लूंग । ड्रोन की बिक्री पूरी की , और बाद में, अबू धाबी 2017 में विंग लूंग ॥ ड्रोन के लिए पहला निर्यात ग्राहक बन गया।

चीन का L15 एडवांस्ड ट्रेनर जेट का निर्यात

फरवरी 2023 में, चीन ने आधिकारिक तौर पर घरेलू स्तर पर विकसित L15 उन्नत ट्रेनर जेट को संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करने के लिए एक सौदे की घोषणा की। L15 बहुमुखी हल्के हमले और लड़ाकू ट्रेनर जेट की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जो महत्वपूर्ण हवा से हवा में युद्ध और भूमि हमले मिशनों को निष्पादित करते समय चौथी और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम है।

चीन-यूएई रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय भूराजनीति

यूएई के रक्षा क्षेत्र में चीन की बढ़ती भागीदारी ने अमेरिकी अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच संभावित गहरे संबंधों का संकेत देता है। अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी होने के बावजूद, सैन्य अभ्यास और हथियार सौदों में चीन के साथ यूएई का सहयोग क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत देता है।

महिलाओं और महिला सेल के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं पर दिशानिर्देश

उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के प्रयास में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "महिलाओं और महिला सेल के लिए एक सुरक्षित वातावरण के लिए बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं पर दिशानिर्देश" विकसित किए हैं। ये दिशानिर्देश एचईआई में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करते हैं। व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता को पहचानते हुए, यूजीसी छात्रों और कर्मचारियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है।

निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप , यूजीसी ने सभी एचईआई को एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाना अनिवार्य कर दिया है। यह समिति शैक्षणिक संस्थानों के भीतर यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी कदाचार या उत्पीड़न को रोकने और निवारण के लिए उचित उपाय किए जाएं।

एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन

निवारण की सुविधा के लिए , यूजीसी ने एक टोल-फ्री नंबर, 1800-111-656 स्थापित किया है। यह हेल्पलाइन किसी भी व्यक्ति के लिए एक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करती है जो उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करना चाहता है या संबंधित

मुद्दों पर मार्गदर्शन चाहता है। टोल-फ्री नंबर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की यूजीसी की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

यौन उत्पीड़न के लिए यूजीसी विनियम

यूजीसी ने विशिष्ट नियम भी पेश किए हैं, जिन्हें यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 के रूप में जाना जाता है। ये नियम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और इसे रोकने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। , यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाएं और उनका समाधान करें। स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करके, यूजीसी ऐसी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाना चाहता है।

लिंग संवेदीकरण को बढ़ावा देना

सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने के लिए लिंग संवेदीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे संबोधित करने के लिए, यूजीसी लिंग संवेदीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, HEI में सेमिनार, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। लैंगिक मुद्दों, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों की समझ को बढ़ावा देकर, यूजीसी का लक्ष्य परिसर में सम्मान, समानता और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

छात्रों और कर्मचारियों को लक्षित करने वाली समावेशी पहल

यूजीसी की पहल एचईआई में छात्रों और कर्मचारियों दोनों सहित सभी महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई है। इन विशिष्ट समूहों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करके, यूजीसी शैक्षणिक संस्थानों के भीतर उनके समग्र अनुभव को बढ़ाना चाहता है।

मेथनॉल से हाइड्रोजन उत्पादन की नई उत्प्रेरक प्रक्रिया:

ऊर्जा के सबसे स्वच्छ स्रोतों में से एक माने जाने वाले हाइड्रोजन में हरित ईंधन के रूप में अपार संभावनाएं हैं। परंपरागत रूप से, पानी और मीथेन से शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। हालाँकि, मेथनॉल के साथ उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक नई और आशाजनक विधि विकसित की गई है। यह अभूतपूर्व शोध भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरूपति के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था , जिसने टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

नवोन्वेषी विधि में हल्के परिस्थितियों में उत्प्रेरक के रूप में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध रूथेनियम कॉम्प्लेक्स का उपयोग करना शामिल है। यह स्वच्छ रासायनिक डिहाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया के माध्यम से मेथनॉल से हाइड्रोजन के उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है। हाइड्रोजन स्रोत के रूप में मेथनॉल का उपयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसकी ग्रेविमेट्रिक

हाइड्रोजन सामग्री 12.6% है। इसके अलावा, मेथनॉल H2 और CO2 को अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करने में प्रभावी साबित होता है, जिससे यह स्थानांतरण हाइड्रोजनीकरण और C1 रसायन विज्ञान के लिए एक संभावित स्रोत बन जाता है।

सिंथेटिक कार्बनिक रसायन विज्ञान में वाहक के रूप में हाइड्रोजन

हाइड्रोजन वाहक के रूप में मेथनॉल के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह सिंथेटिक कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है, जहां मुक्त हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाइड्रोजन वाहक के रूप में कार्य करके, मेथनॉल हाइड्रोजन के प्रबंधन को सरल बनाता है, जिससे स्थानांतरण हाइड्रोजनीकरण और C1 रसायन विज्ञान में वृद्धि होती है।

औद्योगिक संश्लेषण में अनुप्रयोग

इस शोध का प्रभाव प्रयोगशाला से परे तक फैला हुआ है, क्योंकि यह औद्योगिक संश्लेषण के लिए एक व्यवहार्य दृष्टिकोण प्रदान करता है। मेथनॉल फीडस्टॉक से मुक्त हाइड्रोजन को मूल्यवान रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स के संश्लेषण में कुशलतापूर्वक नियोजित किया जा सकता है। यह टिकाऊ और किफायती रासायनिक उत्पादन के लिए नए रास्ते खोलता है, जो एक हरित और अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य भविष्य में योगदान देता है।

योजना क्लासिक्स

प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन गृह, पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने विशाल संग्रह के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत, कला और वास्तुकला को संरक्षित और बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। इसकी नवीनतम पेशकशों में, संग्रहणीय श्रृंखला ' योजना क्लासिक्स' प्रमुख है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रकाशन प्रभाग, राष्ट्र निर्माण और इतिहास से लेकर जीवनियां और बच्चों के साहित्य तक विभिन्न विषयों पर ज्ञान का प्रसार करने के लिए समर्पित है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और राष्ट्रीय नेताओं के उल्लेखनीय योगदान को प्रदर्शित करने की उनकी प्रतिबद्धता उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं के व्यापक संग्रह के माध्यम से स्पष्ट है।

' योजना क्लासिक्स' का परिचय

उनकी नवीनतम पहलों में से एक संग्रहणीय श्रृंखला ' योजना क्लासिक्स' है, जो लोकप्रिय विकास मासिक, योजना में 1957 से चुनिंदा प्रकाशनों से तैयार किए गए मनोरम कार्यों का खजाना है । यह श्रृंखला न केवल वर्षों से प्रकाशित सामग्री की मंत्रमुग्ध कर देने वाली समृद्धि और विशालता को प्रदर्शित करती है, बल्कि पाठकों को भारत की कला, संस्कृति और विरासत की दुनिया में एक समृद्ध यात्रा भी प्रदान करती है।

' योजना क्लासिक्स' का जश्न

योजना क्लासिक्स' का शुभारंभ दिल्ली पुस्तक मेला 2023 में इसके विमोचन के साथ हुआ। श्री केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा सम्मानित गणमान्य व्यक्ति थे जिन्होंने इस बहुप्रतीक्षित संग्रहणीय श्रृंखला का उद्घाटन किया। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर उनके दौरे के दौरान महानिदेशक सुश्री भी मौजूद थीं । अनुपमा भटनागर , और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

समृद्ध संग्रह की खोज

दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर आगंतुक इतिहास, विरासत और जीवनियों सहित विविध विषयों को शामिल करने वाली पुस्तकों के उत्कृष्ट संग्रह से मंत्रमुग्ध हो गए। राष्ट्रपति पर प्रीमियम पुस्तकें भवन और राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चयनित भाषण भी केवल प्रकाशन विभाग के लिए प्रदर्शित किए गए।

पत्रिकाओं की दुनिया में डूबना

किताबों के साथ-साथ, स्टॉल पर योजना , कुरूक्षेत्र , आजकल और बाल जैसी व्यापक रूप से प्रसारित पत्रिकाओं की एक श्रृंखला भी उपलब्ध थी। भारती . इन पत्रिकाओं में प्रस्तुत व्यापक अंतर्दृष्टि छात्रों, शिक्षाविदों और कला और संस्कृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए मूल्यवान हैं।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, लोक सभा में पेश किया गया जम्मू-कश्मीर में चार समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने के उद्देश्य से 26 जुलाई को सभा । इस विकास ने क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के बीच रुचि और आंदोलन दोनों पैदा किया है।

विधेयक में चार समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का प्रावधान है: गद्दा ब्राह्मण, कोली , पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह। प्रस्तावित समावेशन इन समुदायों की विशिष्ट पहचान को स्वीकार करने और उन्हें विशिष्ट लाभ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गुज्जर और बकरवाल - प्रमुख एसटी समुदाय

जम्मू और कश्मीर में, गुज्जर और बकरवाल प्रमुख एसटी समुदाय हैं। लगभग 18 लाख की संयुक्त आबादी के साथ, वे कश्मीरियों और डोगराओं के बाद इस क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा समूह हैं । 1991 में गुज्जर-बकरवाल समुदाय को दिए गए एसटी दर्जे से उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिला।

बीच में आंदोलन गुज्जर-बकरवाल नेता

पहाड़ी जातीय समूह और पद्दारी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करने के प्रस्तावित प्रस्ताव ने गुज्जर-बकरवाल समुदाय के बीच अशांति फैला दी है। उन्हें चिंता है कि विस्तार से कोटा लाभ पाई में उनकी हिस्सेदारी में कमी आ सकती है ।

गुज्जर-बकरवाल नेताओं का तर्क है कि गद्दा ब्राह्मण और कोली , जो पहले से ही एसटी सूची का हिस्सा हैं, नए समुदायों के साथ समानताएं साझा करते हैं।

पहाड़ी लोगों की एसटी दर्जे की तलाश

पहाड़ी जातीय समूह के लिए एसटी दर्जे की मांग 1989 से चली आ रही है जब जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन्हें शामिल करने की सिफारिश की थी। हालाँकि, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की कमी का हवाला देते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बार-बार प्रयासों के बावजूद, मामले को कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जीडी शर्मा आयोग की सिफारिश

पहाड़ी जातीय समूह और अन्य समुदायों के लिए सफलता 2019 में आई जब न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जीडी शर्मा आयोग ने गद्दा ब्राह्मणों, कोलियों , पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह के लिए एसटी दर्जे की सिफारिश की। आयोग की रिपोर्ट में इन समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डाला गया।

G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रिस्तरीय बैठक

28 जुलाई, 2023 को चेन्नई में आयोजित G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रिस्तरीय बैठक, महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों को संबोधित करने के लिए विश्व नेताओं की एक महत्वपूर्ण सभा थी। हालाँकि, जैसे ही बैठक समाप्त हुई, कई प्रमुख चुनौतियाँ सामने आईं क्योंकि देश महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर आम सहमति तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

जी20 बैठक के दौरान चर्चा में प्रमुख मुद्दों में से एक जीवाश्म ईंधन से दूर जाना था। दुर्भाग्य से, भाग लेने वाले देश इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक समझौते पर नहीं आ सके। इसके महत्व के बावजूद, इस विषय का उल्लेख केवल अध्यक्ष के सारांश में किया गया, जहां इसे 'निरंतर जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने' के रूप में संदर्भित किया गया था। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर समझौते की कमी ने जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दीं।

नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन शिखर पर आम सहमति नहीं बनी

जी20 बैठक दो महत्वपूर्ण जलवायु उद्देश्यों - नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाना और प्रारंभिक वैश्विक उत्सर्जन चरम पर पहुंचना - पर एक समझौते पर पहुंचने में असफल रही। ये दोनों लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, देशों के बीच मतभेद, विशेष रूप से महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन हितों वाले देशों के बीच, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकीकृत रुख तक पहुंचने में प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से रुकावट

चीन, सऊदी अरब और रूस को प्रमुख देशों के रूप में पहचाना गया जिन्होंने ऊर्जा परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं का विरोध किया। इन देशों के प्रतिरोध ने वार्ता को और जटिल बना दिया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से निपटने की चुनौती को उजागर किया जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर अपने स्वार्थों को प्राथमिकता दे सकती हैं।

जलवायु वित्त पुनः पुष्टि

जी20 बैठक का एक सकारात्मक परिणाम जलवायु वित्त लक्ष्यों की पुनः पुष्टि थी। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि परिणामों ने केवल जलवायु वित्त की माँगों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर हल्का जोर दिया। जलवायु परिवर्तन और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण के अनुकूलन के विकासशील देशों के प्रयासों में सहायता के लिए जलवायु वित्त आवश्यक है। फीकी पुनर्पुष्टि से संकेत मिलता है कि दुनिया भर में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए अधिक मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है।

ऊर्जा संक्रमण के लिए तकनीकी प्रस्ताव

विभिन्न जलवायु मुद्दों पर आम सहमति की कमी के बावजूद, परिणाम दस्तावेज़ ने ऊर्जा संक्रमण के लिए कुछ पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रस्ताव दिया। इनमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, डायरेक्ट एयर कैप्चर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के साथ बायोएनर्जी शामिल थी। हालाँकि, चिंताएँ पैदा हुईं क्योंकि इन सुझावों ने विभिन्न देशों की अलग-अलग क्षमताओं और आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए, इन प्रौद्योगिकियों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता मान ली।

बिखरा हुआ फोकस और भू-राजनीतिक प्रभाव

सम्मेलन के नतीजे बिखरे हुए दिखाई दिए, जो भूमि क्षरण, जैव विविधता, नीली अर्थव्यवस्था, परिपत्र अर्थव्यवस्था, प्लास्टिक और जल प्रबंधन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण लेकिन मूर्त रूप से संबंधित विषयों पर केंद्रित थे। स्पष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण की कमी ने गंभीर जलवायु चुनौतियों से निपटने की प्रभावशीलता को कम कर दिया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (MASAI) परीक्षण के साथ मैमोग्राफी स्क्रीनिंग

स्तन कैंसर एक प्रचलित स्वास्थ्य चिंता है जो दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित कर रही है। प्रारंभिक चरण में स्तन कैंसर का पता लगाना सफल उपचार और बेहतर रोगी परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। लुंड यूनिवर्सिटी, स्वीडन के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व शोध अध्ययन ने मैमोग्राफी स्क्रीनिंग में क्रांति लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की क्षमता पर प्रकाश डाला है। द लैंसेट ऑन्कोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से आशाजनक परिणाम सामने आए हैं जो स्तन कैंसर का पता लगाने की दर और रेडियोलॉजिस्ट के कार्यभार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

स्तन कैंसर का पता लगाने में एआई के प्रभाव का खुलासा

अध्ययन में एआई-समर्थित मैमोग्राफी स्क्रीनिंग की प्रभावशीलता की तुलना मानक स्क्रीनिंग विधियों से की गई। शोध के प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह है कि एआई-समर्थित मैमोग्राफी ने पारंपरिक स्क्रीनिंग तकनीकों की तुलना में एक-पांचवें (20%)

अधिक स्तन कैंसर का पता लगाया है। यह रेडियोलॉजिस्ट की क्षमताओं को बढ़ाने और कैंसर का पता लगाने की दर में सुधार करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में एआई की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

रेडियोलॉजिस्ट के लिए बोझ हल्का करना

नियमित रूप से बड़ी मात्रा में मैमोग्राम का विश्लेषण करने की आवश्यकता के साथ, रेडियोलॉजिस्ट पर बोझ काफी है । हालाँकि, अध्ययन इस संबंध में एक आशाजनक सफलता सामने लाता है। एआई-समर्थित स्क्रीनिंग से रेडियोलॉजिस्ट के लिए स्क्रीन-रीडिंग कार्यभार को प्रभावशाली ढंग से 44% कम पाया गया। यह कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अधिक कुशल जांच, त्वरित निदान और रेडियोलॉजिस्ट की विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग हो सकता है।

अध्ययन का आकार और दायरा

शोध अध्ययन में पर्याप्त नमूना आकार शामिल था, जो इसके प्रभाव की भयावहता को दर्शाता है। अध्ययन में कुल 80,000 स्वीडिश महिलाओं ने भाग लिया। इन महिलाओं को बेतरतीब ढंग से दो समूहों में आवंटित किया गया था - एक हस्तक्षेप समूह जिसमें 40,003 महिलाएं शामिल थीं, जिनकी एआई-समर्थित स्क्रीनिंग हुई थी, और एक नियंत्रण समूह जिसमें 40,030 महिलाएं शामिल थीं, जो मानक स्क्रीनिंग से गुजरी थीं।

जांच दर और कैंसर का पता लगाना

अध्ययन ने दोनों समूहों में कैंसर का पता लगाने की दर को सावधानीपूर्वक दर्ज किया। एआई-समर्थित स्क्रीनिंग समूह की कुल 244 महिलाओं (28%) में स्तन कैंसर पाया गया। इसकी तुलना में, मानक स्क्रीनिंग समूह की 203 महिलाओं (25%) में स्तन कैंसर का निदान किया गया था। एआई-समर्थित स्क्रीनिंग से 41 और कैंसर का पता चला, जो शीघ्र निदान में सुधार करने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है।

झूठी-सकारात्मक दरें और एआई सटीकता

स्तन कैंसर की जांच में गलत-सकारात्मक परिणाम रोगियों के लिए अतिरिक्त तनाव और अनावश्यक अनुवर्ती प्रक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। हालाँकि, अध्ययन से पता चला कि एआई-समर्थित स्क्रीनिंग समूह और मानक स्क्रीनिंग समूह दोनों में झूठी-सकारात्मक दर 1.5% पर स्थिर रही, जो एआई-संवर्धित मैमोग्राफी की सटीकता और सुरक्षा की पुष्टि करती है।

एआई-समर्थित स्क्रीनिंग: संख्याओं को संभालना

अध्ययन में एआई समर्थन से संसाधित मैमोग्राम की विशाल मात्रा का पता लगाया गया। एआई-समर्थित स्क्रीनिंग समूह में, कुल 46,345 स्क्रीन रीडिंग आयोजित की गईं। यह मानक स्क्रीनिंग समूह में की गई 83,231 स्क्रीन रीडिंग की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था। स्क्रीन रीडिंग में कमी स्तन कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में एआई कार्यान्वयन की दक्षता और संभावित लागत-प्रभावशीलता पर और जोर देती है।

आयुष वीजा

गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक नई वीज़ा श्रेणी शुरू की है जिसे " आयुष वीज़ा" के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह वीज़ा आयुष प्रणालियों या भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग सहित विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपचार की तलाश करने वाले विदेशी नागरिकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आयुष वीजा विदेशी नागरिकों को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध और होम्योपैथी सहित चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इस वीज़ा श्रेणी का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के उन व्यक्तियों को आकर्षित करना है जो भारत में पेश किए जाने वाले विशेष चिकित्सा उपचार की तलाश करते हैं। इसमें समग्र कल्याण, वैकल्पिक उपचार और प्राकृतिक उपचार विधियों की तलाश करने वाले लोग शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

आयुष वीज़ा पहल ऐसे समय में आई है जब वैश्विक कल्याण अर्थव्यवस्था 9.9% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेजी से विकास का अनुभव कर रही है । 2025 तक, आयुष आधारित स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण अर्थव्यवस्था प्रभावशाली $70 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह भारत के लिए चिकित्सा पर्यटन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की अपार क्षमता को दर्शाता है।

सहयोगात्मक प्रयास

आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए । सहयोग का उद्देश्य आयुर्वेद और चिकित्सा के अन्य पारंपरिक रूपों की प्रमुखता को बढ़ाना है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए और अधिक सुलभ बनाया जा सके।

आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संयुक्त रूप से "हील इन इंडिया" पोर्टल विकसित कर रहे हैं। यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेगा, जो विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध उपचार, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और वीज़ा आवश्यकताओं के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा।

भविष्य के लक्ष्य

भविष्य को देखते हुए, असम सरकार अपने पौधारोपण प्रयासों का विस्तार करने की योजना बना रही है। अगले वर्ष 3 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाने का लक्ष्य है और 2025 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। ये प्रगतिशील लक्ष्य राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने और इसकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

असम लकड़ी आधारित उद्योग (संवर्धन और विकास) नियम 2022

अमृत के अतिरिक्त बृक्ष्य आंदोलन में , मुख्यमंत्री ने असम लकड़ी-आधारित उद्योग (संवर्धन और विकास) नियम 2022 भी पेश किया। यह 2000 के पहले के असम लकड़ी-आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम की जगह लेता है। नए नियम स्वदेशी के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं पिछले नियमों द्वारा लगाई गई बाधाओं को दूर करके लकड़ी आधारित उद्योग।

अगरवुड उत्पादकों को लाभ

नए नियम असम में अगरवुड उत्पादकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहे हैं। अब वे घरेलू इकाइयों में अगर तेल के प्रसंस्करण की अनुमति देते हैं, जिससे ऊपरी असम में उत्पादकों को महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। इस कदम से अगरवुड की खेती में शामिल किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है ।

विवाद से विश्वास 2 :

सरकार और उसके उपक्रमों से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, वित्त मंत्रालय ने " विवाद से विश्वास 2" योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और समय पर निपटान सुनिश्चित करते हुए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

विवाद से विश्वास 2 योजना भारत सरकार और उसके नियंत्रण में काम करने वाले संगठनों के बीच संविदात्मक विवादों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक निपटान प्रणाली है । यह योजना अपने पूर्ववर्ती का विस्तार है, जिसका उद्देश्य विवादों को सुलझाने और व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है।

प्रयोज्यता और समय सीमा

इस योजना के तहत 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को कवर किया जाएगा, जिससे काफी संख्या में लंबित मामले इसके दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान निष्पक्ष और कुशल विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए योजना की शुरुआत की घोषणा की।

निपटान की शर्तें

शीघ्र निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए, योजना विवाद के लंबित स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों की पेशकश करती है। 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले पारित किए गए अदालती पुरस्कारों के लिए, ठेकेदारों को अदालत द्वारा दी गई या बरकरार रखी गई कुल राशि का 85% तक निपटान राशि की पेशकश की जाएगी। इसी प्रकार, 31 जनवरी 2023 को या उससे पहले पारित मध्यस्थ पुरस्कारों के लिए, प्रस्तावित निपटान राशि प्रदान की गई शुद्ध राशि का 65% तक होगी।

GeM के माध्यम से निर्बाध कार्यान्वयन

योजना के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, व्यय विभाग ने 29 मई 2023 को " विवाद से विश्वास 2 (संविदात्मक विवाद)" के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक विशेष वेबपेज पूरी तरह से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) द्वारा स्थापित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना कि इसके माध्यम से केवल पात्र दावों पर ही कार्रवाई की जाएगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और समाधान में तेजी लाना है।

स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) पोर्टल

ने भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्टडी इन इंडिया (SII) पोर्टल लॉन्च किया। इस मंच का उद्देश्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की यात्रा को सरल बनाना है, जिससे उन्हें मूल्यवान शैक्षिक अवसरों तक निर्बाध पहुंच प्रदान की जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का स्वागत: एक साझा दृष्टिकोण

स्टडी इन इंडिया (SII) पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने किया प्रधान . इस पहल के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विविध पृष्ठभूमि के छात्रों का स्वागत करना है। देश को एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में समर्थन देकर, भारत शिक्षा क्षेत्र में एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति स्थापित करना चाहता है।

आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना

SII पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनकी आवेदन प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पंजीकरण से लेकर वीज़ा अनुमोदन तक, प्लेटफ़ॉर्म एक सहज इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो उनकी पूरी यात्रा को सरल बनाता है। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया छात्रों को प्रशासनिक जटिलताओं से घिरे बिना अपनी शैक्षणिक आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्देशित

स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) पोर्टल का दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गहराई से निहित है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एनईपी भारत को एक पसंदीदा शिक्षा गंतव्य बनाने के दृष्टिकोण को आकार देने में सहायक है। पोर्टल का लक्ष्य शैक्षणिक सीमाओं को पार करना और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों छात्रों के लिए समृद्ध भविष्य को बढ़ावा दे।

वैश्विक शिक्षा के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम

2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया SII कार्यक्रम, एक प्रमुख परियोजना है जिसका स्पष्ट उद्देश्य भारत को एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में समर्थन देना है। शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करके, कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए देश में मूल्यवान शैक्षिक अवसरों का पता लगाने के द्वार खोलता है।

घरेलू छात्रों के लिए लाभ

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की उपस्थिति भारत में घरेलू छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। विविध संस्कृतियों के साथियों के साथ बातचीत करके, छात्र वैश्वीकरण की दुनिया की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह एक्सपोज़र उन्हें वैश्विक कार्यस्थल के लिए बेहतर ढंग से तैयार करता है, एक परस्पर जुड़ी दुनिया में उनकी संभावनाओं को बढ़ाता है।

सद्भावना के दूत

भारत में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र देश के लिए सद्भावना के राजदूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में उनके अनुभव राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंध बनाते हैं, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। जैसे ही वे अपने मूल समाज में लौटते हैं, वे भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का सार लेकर आते हैं, जिससे वैश्विक संबंध मजबूत होते हैं।

एक लाइन

- इसरो ने सिंगापुर के डीएस-एसएआर और छह अन्य उपग्रहों को ले जाने वाले पीएसएलवी-सी56 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- स्वच्छता पर डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक मोबाइल ऐप अभियान , देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग के 6,253 मामलों की पहचान करता है।
- महाराष्ट्र बुनियादी ढांचे के उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए विश्व बैंक की सहायता चाहता है।
- बिजली मंत्रालय ने राज्यों द्वारा लेखांकन, बिलिंग और सब्सिडी भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया
- एडीबी और केंद्र सरकार ने राजस्थान में शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
- तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 600 किलोग्राम के खाने के पैकेट गिराए ।
- नीलगिरी में राष्ट्रीय कीट सप्ताह (22 जुलाई और 28 जुलाई) मनाया गया ।
- 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं लापता हो गईं: सरकारी डेटा।
- छह करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया था: आईटी विभाग।
- भारत 2030 तक 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ मध्यम आय वाला देश बन जाएगा: रिपोर्ट

- पीएफआरडीए ने वार्षिकी व्यवसाय के लिए बिचौलियों पर रोक लगा दी है।
- भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2,450 अमेरिकी डॉलर से लगभग 70% बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 4,000 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।
- फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए टीएन के साथ ₹1,600 करोड़ का सौदा किया ।
- दो भारतीय सैन्य विमानों ने ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक कोकोस द्वीप समूह का दौरा किया।
- अफ्रीकी नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दो दिवसीय बैठकें बिना अनाज समझौते के छोड़ रहे हैं।
- मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह में मतदान शुरू किया।
- थाईलैंड के गोदाम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 10 हो गई।
- टेनिस: इगा स्विएटेक ने लौरा सीगमुंड को हराकर वारसॉ ओपन जीता।
- 2023 F1 बेल्जियम ग्रां प्री: वेरस्टैपेन ने लगातार आठवीं जीत हासिल की।
- भारतीय महिलाओं ने स्पेन को 3-0 से हराकर स्पेनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया।
- प्रधानमंत्री आवास के तहत 75.51 लाख घर पूरे किये गये योजना (PMAY-U) कार्यक्रम.
- पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मणिपुर में हिंसा की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया.
- ओबीसी आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी को उप-वर्गीकरण रिपोर्ट सौंपी मुर्मू .
- इसरो ने चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया।
- जी-20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर में शुरू होगा ।
- पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य सम्मान प्रदान किया देश की प्रगति में योगदान के लिए तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार।
- भारत के मुख्य क्षेत्र की वृद्धि दर जून में पांच महीने के उच्चतम स्तर 8.2% पर पहुंच गई।
- इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
- श्रीलंका की प्रमुख मुद्रास्फीति दर जुलाई में लगभग आधी होकर 6.3% हो गई, जो पिछले महीने 12% थी।
- वलोडिमिर में एक अपार्टमेंट और एक विश्वविद्यालय की इमारत से टकराईं ज़ेलेंस्की का गृहनगर।
- पाकिस्तान: राजनीतिक सम्मेलन में आत्मघाती विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई।
- CPEC के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में, पाकिस्तान और चीन ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति छह महीने के लिए बढ़ा दी है।
- सात वर्षों में पहला परमाणु रिएक्टर अमेरिका के जॉर्जिया में सेवा में शामिल हुआ।
- क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में हेडर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
- डब्ल्यूटीए रैंकिंग: पोलिश टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने सप्ताह 70 की शुरुआत विश्व नंबर 1 के रूप में की
- डेटा: भारत में महिलाएं सात घंटे और पुरुष तीन घंटे से कम घरेलू काम करते हैं।

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से शवों को लाने के लिए ई-क्लीयरेंस पोर्टल शुरू करने की घोषणा की।
- बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण फिर शुरू।
- केंद्र ने परिसरों में भेदभाव विरोधी दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया।
- सुप्रीम कोर्ट: अनुच्छेद 370 को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास बरकरार।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 2 लाख करोड़ से अधिक का अब तक का उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया।
- जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स वसूलने की अपनी योजना पर कायम है।
- केंद्र ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया।
- केंद्र राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार (एनएमए) 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और एलएसी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 50 बिलियन डॉलर हो गया।
- बीजिंग में '140 वर्षों में सबसे भारी वर्षा' हुई है
- चीन के साइबरस्पेस वॉचडॉग ने बच्चों के स्मार्टफोन के समय को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है।
- थाईलैंड की मूव फॉरवर्ड पार्टी (एमएफपी) को सरकार बनाने के लिए गठबंधन से बाहर रखा गया है।
- बैडमिंटन: किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
- एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप आज से शुरू होगा।
- हॉकी: 7वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू होगी।